(घ) जी, हां। बैंक ने सूचित किया है कि एक माननीय संसद सदस्य ने भारतीय स्टेट बैंक, मालवीय नगर शाखा, नई दिल्ली के ग्राहक सेवा के बारे में एक शिकायत दर्ज कराई है। बैंक ने वास्तविक स्थिति का पता लगाने हेतु जांच प्रारम्भ की है ताकि उपयुक्त उपचारात्मक कार्रवाई को जा सके।

Decline in Branches of Banks in Rural Areas

1490. SHRI NAGMANI:
SHRI ISH DUTT YADAV:

Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether the number of banks branches have declined in rural areas;

(b) if so, the details thereof; and

(c) the reasons of this decline and the percentage of this decline during the last three years?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI SATPAL MAHARAJ) (a) to (c) The number of rural branches of scheduled commercial banks in the country and the percentage of such branches to total branches as at the end of March 1995, March 1996 and March 1997, as furnished by Reserve Bank of India (RBI) are given below:—

As at the end of	No. of rural branches	Percentage of rural branches to total branches
March, 1995	33011	53.0
March, 1996	33015	52.4
March, 1997	33024	52.2

The number of rural branches has increased during the period.

विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम संबंधी मामलों के निपटारे के लिए विशेष अदालतें

1491. **श्री ईश दत्त यादव**:
श्री नागमणि :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, संबंधी मामलों को अतिशीघ्र निपटाने हेतु विशेष अदालतें स्थापित करने का विचार कर रही है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) से (ग) विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के मामलों के लिए विशेष न्यायालय स्थापित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन नहीं है।

लघु वृहत् और मध्यम उद्योगों को ऋण देने संबंधी भारतीय रिजर्व बैंक का अध्ययन

1492. **श्री राय जेठमलानी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रिजर्व बैंक ने ऐसा कोई अध्ययन किया है, जिससे यह पता चलता हो कि वृहत् और मध्यम श्रेणी के उद्योगों को ऋण देने की अपेक्षा लघु उद्योगों को ऋण प्रदान करना कम जोखिम भरा है,

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है,

(ग) क्या सरकार ने लघु उद्योग क्षेत्र और वृहत् एंव मध्यम श्रेणी के उद्योगों को दिए गए ऋणों के पुनः भुगतान का कोई ब्यौरा प्राप्त किया है, और

(घ) यदि हां, तो विगत तीन वर्षो के दौरान ऋण के पुनः भुगतान का प्रतिशत क्या रहा और मार्च 1997 में दोनों क्षेत्रों में गैर-कार्यक्षम सम्पत्ति की मात्रा क्या रही?